National Journal of Multidisciplinary ResearchAnd Development
www.multidisciplinaryjournal.org
ISSN: 2455-9040
Received: 15-09-2023, Accepted: 01-10-2023, Published: 17-10-2023
Volume 8, Issue2, 2023, Page No. 153-159

भारत में विमुद्रीकरणः वरदान या अभिशाप

नीलिमा[1], बृजलता शर्मा[2]
[1] शोद्यार्थी, हिंदी विभाग, महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड, भारत
[2] प्रोफेसर, हिंदी विभाग, महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड, भारत

सारांश

नोटबंदी / नोटबदली / विमुद्रीकरण नीति का भारतीयों के सामाजिक– सांस्कृतिक– राजनीतिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर संक्षिप्त परिचय

- देश के सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक ताने–बाने और राष्ट्रीय गतिशीलता पर इसके असाधारण प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करे तो पाएंगे कि नवंबर 2016 में, भारत सरकार ने भ्रष्टाचार का मुकाबला करने, काले धन को खत्म करने और नकली मुद्रा के संचलन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उच्च–मूल्य वाले करेंसी नोटों को विमुद्रीकृत करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया। इस कठोर कदम के व्यापक परिणाम हुए जिसने भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव छोड़ा।
- भारत में विमुद्रीकरण के इस ऐतिहासिक निर्णय लेने से लाखों नागरिकों के दैनिक जीवन को बाधित कर दिया था। विमुद्रीकरण नीति के क्रियान्वयन से तत्काल परिणामस्वरूप पूरे देश में देखे गए अराजक दृश्यों का वर्णन करना; वो भी निर्धारित शब्द सीमा में बहुत कठिनाई भरा कार्य है। इस नियम के चलते लोग सीमित समय सीमा के भीतर अपने पुराने नोटों को बदलने के लिए दौड़ पड़े। वित्तीय उथल–पुथल की इस अवधि के दौरान सामान्य आबादी द्वारा अनुभव किए गए तनाव और चिंता को उजागर करते हुए, सामाजिक संपर्क, पारिवारिक गतिशीलता और व्यक्तिगत व्यवहार पर प्रभावी अंकुश की स्थिति समाज में व्याप्त हो गई थी।
- भारत में विमुद्रीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों जैसे शादियों, धार्मिक प्रसाद और अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों सहित भारतीय समाज के ताने–बाने में गहराई से शामिल नकद लेन–देन की पारंपरिक प्रथाओं की जांच करते हुए, नकदी की अचानक अनुपलब्धता के कारण हुए व्यवधान तथा यह पता लगाने के लिए कि व्यक्तियों और समुदायों ने वैकल्पिक भुगतान विधियों और डिजिटल लेन–देन को कैसे अपनाया। उन दिनों में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जो भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य का सदैव से एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
- प्रस्तुत लेख समग्र रूप से राष्ट्र की धारणा पर विमुद्रीकरण के प्रभाव की पड़ताल करते हुए इस नीति के प्रति भारत की जनता की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने वाले सभी तत्वों; जिसमें जनता की भावना, विरोध और सरकार की पहल के लिए समर्थन आदि अभिव्यक्ति को आधार बनाकर विचार–विमर्श को शामिल किया गया है। इस लेख द्वारा इस बात की पड़ताल करने में पाठकों को मदद मिलेगी कि कैसे विमुद्रीकरण राजनीतिक बहसों, मीडिया आख्यानों और सार्वजनिक विमर्श में चर्चा का एक प्रमुख विषय बन गया, जिसने उस अवधि के दौरान राष्ट्रीय आख्यान को भी एक आकार दिया।
- यहॉ इस शोध पत्र के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक संकेतो पर विमुद्रीकरण के दीर्घकालिक परिणामों की जांच पर भलि–भांति प्रकाश डालने की कोशिश की गई है। यहां इस आकलन से पता चलता है कि नीति ने भ्रष्टाचार को रोकने, अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने और डिजिटल लेन–देन को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्यों को किस हद तक सफलता प्राप्त की है। भारत के वित्तीय परिदृश्य में विमुद्रीकरण द्वारा लाए गए परिवर्तनकारी परिवर्तनों को उजागर करते हुए, वित्तीय समावेशन, तकनीकी अपनाने और फिनटेक स्टार्टअप्स के उदय पर प्रभाव का भी विश्लेषण किया गया है।
  यह व्यापक योजना, प्रभावी संचार और समाज के कमजोर वर्गों पर प्रतिकूल प्रभावों के शमन की आवश्यकता पर बल देता है। यह लेख भारत में व्यापक वित्तीय सुधारों के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में विमुद्रीकरण की भूमिका की भी पड़ताल करता है, जैसे कि माल और सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत करके कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर धकेलना।
- अतः हम यहां इसी उद्देश्य से विचार कर रहे हैं कि भारतीय समाज, संस्कृति और राष्ट्रीय गतिशीलता पर विमुद्रीकरण के असाधारण प्रभाव का गहन विश्लेषण क्या है। इस नीति के कारण हुए अभूतपूर्व व्यवधान की जांच करके, इसका उद्देश्य भारत के हाल के इतिहास में इस परिवर्तनकारी घटना के सामाजिक और सांस्कृतिक निहितार्थों को समझने में रुचि रखने वाले नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और व्यक्तियों के लिए समझ को बढ़ाना और अंतदृष्टि उत्पन्न करना ही, इस शोध पत्र का आधार है।

मूल शब्दः विमुद्रीकरण, सिंहावलोकन, मरीचिका, सुधारोन्मुखी, पारदर्शिता, ग्रे मार्केट

प्रस्तुत लेख भारत में विमुद्रीकरण के प्रभावों की निष्पक्षतापूर्ण जांच करता है। राष्ट्र के लिए वरदान या अभिशाप के रूप में इसके समग्र प्रभाव का मूल्यांकन करता है। नवंबर 2016 में, तत्कालिन भारत सरकार ने भ्रष्टाचार, काले धन और जाली मुद्रा पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उच्च मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण (Demonetization) करके एक साहसिक और अभूतपूर्व कदम उठाया। हालाँकि, इस कठोर निर्णय के दूरगामी परिणाम भी देखने को मिले ,जिसने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और लाखों नागरिकों के जीवन को प्रभावित भी किया।

विमुद्रीकरण एक ऐसी आर्थिक क्रांति है जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी उपयोग में लायी जा रही मुद्रा को समाप्त करके उसकी जगह , एक नई मुद्रा को लागू करती है। जब–जब देश में काला धन बढ़ता है तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की स्थिति बन जाती है।ऐसी परिस्थिति में इस समस्या के निवारण

हेतु विमुद्रीकरण का उपाय ही एकमात्र महत्त्वपूर्ण भूमिका अभिनीत करता है।

लेख के आरंभ में ही सरकार के निर्णय और उसके उद्देश्यों के पीछे के तर्क पर चर्चा करते हुए विमुद्रीकरण नीति का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत करने जैसी स्थिति को प्रकाश में लाने का प्रयत्न शब्दों के रूप में किया गया है। इसके बाद, यह लेख भारत की 86% मुद्रा के संचलन में अचानक वापसी के कारण हुई अराजकता और व्यवधान को उजागर करते हुए, तत्काल परिणाम पर प्रकाश डालते हुए छोटे–छोटे व्यवसायों, किसानों और दैनिक वेतन भोगियों पर प्रतिकूल प्रभाव के विश्लेषण को भी उजागर करता है, जो समाज के कमजोर वर्गों द्वारा सामना की जाने वाली अपार कठिनाइयों का एक वास्तविक निचोड़ है।

इसके अतिरिक्त प्रस्तुत लेख में कृषि, विनिर्माण और रियल एस्टेट जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विमुद्रीकरण के दीर्घकालिक प्रभावों की पड़ताल भी करने का प्रयास किया गया है। यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणामों पर विचार करते हुए खपत की प्रक्रिया, निवेश के रुझानों और रोजगार के अवसरों में बदलाव की जांच भी ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकाल कर विचारकों की राय को भी प्रस्तुत लेख में दर्शाने वाले तथ्यों को प्रकट करता है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल भुगतान पर प्रभाव और अर्थव्यवस्था के औपचारिककरण की जांच भी की जाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि विमुद्रीकरण ने अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त किया है या नहीं।

अब आगे बात करते हैं समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, काले धन और अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण से निपटने में विमुद्रीकरण की प्रभावशीलता का आंकलन और क्रियान्वयन प्रक्रिया के दौरान सामने आने वाली विभिन्न कमियों और चुनौतियों पर विचार करते हुए, यह लेख जांच करता है कि इन अवैध प्रथाओं को किस हद तक रोका गया था, साथ ही इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई। यह भी सुनिश्चित करना अति आवश्यक है कि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में आधार और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी तकनीकी प्रगति की क्या भूमिका रही।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तुत लेख में भारतीय समाज पर विमुद्रीकरण के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव की भी जांच–पड़ताल करने वाले आचार–विचार को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। प्रस्तुत लेख में नोटबन्दी – नोटबदली नियम के प्रति जनता की धारणा और सरकार के आर्थिक निर्णयों में समग्र विश्वास का विश्लेषण किया गया है।

विमुद्रीकरण के व्यापक प्रभावों की व्यापक मरीचिका की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए, राजनीतिक गतिशीलता, जन भावना और 2019 के आम चुनावों पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी विचार–विमर्श करने के साथ–साथ वास्तविक स्वरूप को समझते हुए शब्दों में उन तथ्यों को स्पष्ट यहां किया गया है।

अंततरू यह लेख भारत में विमुद्रीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों को देखते हुए इसका संतुलित मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।साथ ही वैश्विक पटल पर कब– कब दूसरे देशों द्वारा भी विमुद्रीकरण की नीति को अपनाया गया। प्रस्तुत लेख इस महत्त्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप के आसपास चल रहे प्रयासों में योगदान देना चाहता है, साथ ही नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और शोधकर्ताओं को भारत और उसके बाहर विमुद्रीकरण के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

विमुद्रीकरण: विस्तृत जानकारी

सर्वविदित है कि भारत में विमुद्रीकरण प्रक्रिया के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा मुख्य भूमिका निभाई गई थी। उच्च मूल्य के करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के निर्णय की घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री ने की थी, विभिन्न सरकारी विभाग और एजेंसियां नीति के क्रियान्वयन और प्रबंधन में शामिल थीं। इस नीति को लागू करने से भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र; जैसे–

- विमुद्रीकरण का भारत के विभिन्न करेंट अफेयर्स पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसने कृषि, विनिर्माण, रियल एस्टेट और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों को प्रभावित किया। संचलन में मुद्रा के एक बड़े हिस्से की अचानक वापसी ने आर्थिक गतिविधियों को बाधित कर दिया, जिससे उत्पादन, रोजगार और खपत में चुनौतियाँ पैदा हो गईं। इस कदम के सामाजिक निहितार्थ भी थे, जिससे व्यक्तियों और समुदायों को असुविधा और कठिनाई होती थी।
- विमुद्रीकरण के क्रिर्यान्वयन से उत्पन्न चुनौतियां और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के जवाब में, वर्तमान सरकार ने अनेक मुद्दों के समाधान हेतु कई उपाय किए हैं। इनमें डिजिटल लेन–देन को बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसे आर्थिक सुधारों को लागू करना आदि शामिल है। सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने, भ्रष्टाचार को कम करने और व्यापार करने में आसानी के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग पर भी जोरदार समर्थन किया है।
- सरकार ने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। नवाचार, रोजगार सृजन और आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए "मेक इन इंडिया", "स्टार्टअप इंडिया", और "डिजिटल इंडिया" जैसी कई पहलें शुरू की गई हैं।
- पिछले दशकों की तुलना में, वर्तमान सरकार ने भारत के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए अधिक सक्रिय और सुधारोन्मुखी दृष्टिकोण पर जोर दिया है। विमुद्रीकरण नीति को भ्रष्टाचार, काले धन और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से निपटने के सरकार के प्रयासों में एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया। हालाँकि, विमुद्रीकरण की प्रभावशीलता और आर्थिक विकास पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव बहस और विश्लेषण का विषय रहा है।

यहां यह ध्यान रखना अति महत्त्वपूर्ण है कि आर्थिक विकास एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है, जो वैश्विक रुझानों, नीतिगत निर्णयों, बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक–आर्थिक कारकों सहित विभिन्न कारकों से प्रभावित है। जबकि विमुद्रीकरण एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप था, यह हालही के वर्षों में भारत के आर्थिक प्रक्षेपवक्र को आकार देने वाले कई कारकों में से एक है। आर्थिक विकास पर विमुद्रीकरण के प्रभाव का आकलन करने के लिए कई संकेतकों और दीर्घकालिक रुझानों के व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता वर्तमान समय में है।

भारत में वित्तीय संकट को देखते हुए, भविष्य में सर्वोत्तम प्रदर्शन हेतु सामाजिक रूप से जिम्मेदार आर.बी.आई. की भूमिका; कार्यरूप में वास्तविकता और मिथक –

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने, सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने और वित्तीय संकटों को दूर करने और भारत में जिम्मेदार वित्तीय प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए भविष्योन्मुखी दिशा–निर्देश प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका –

मौद्रिक नीति निर्माण: आरबीआई मौद्रिक नीतियों को तैयार और कार्यान्वित करता है, जैसे मूल्य स्थिरता बनाए रखने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरें निर्धारित करना।

बैंकिंग विनियमन: आर.बी.आई. भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों की मजबूती और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें नियंत्रित और पर्यवेक्षण करता है। यह जिम्मेदार बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए पूंजी पर्याप्तता, जोखिम प्रबंधन और कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए दिशा–निर्देश जारी व निर्धारित करता है।

वित्तीय क्षेत्र का विकास: आर.बी.आई. नवाचार को प्रोत्साहित करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और कुशल भुगतान प्रणाली की सुविधा प्रदान करके वित्तीय क्षेत्र को विकसित और मजबूत करने की पहल करता है।

संकट प्रबंधन और संकल्प: RBI वित्तीय संकटों के प्रबंधन और बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संकटग्रस्त वित्तीय संस्थानों को संबोधित करने और प्रणालीगत जोखिमों को रोकने के उपायों को तैयार और क्रियान्वित करता है।

वित्तीय समावेशन: आर.बी.आई. बैंकों के लिए दिशा–निर्देश निर्धारित करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है ताकि उनकी पहुंच को कम क्षेत्रों और आबादी तक बढ़ाया जा सके। यह वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और नवीन बैंकिंग मॉडल के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।

उपभोक्ता संरक्षण: आर.बी.आई. बैंक ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए विनियमों और दिशा–निर्देशों को लागू करके उपभोक्ता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। यह निष्पक्ष व्यवहार, पारदर्शी प्रकटीकरण और शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करता है।

विवेकपूर्ण मानदंड: आर.बी.आई. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित करता है, जिसमें प्रावधान संबंधी आवश्यकताएं, परिसंपत्ति वर्गीकरण और जोखिम प्रबंधन ढांचे इत्यादि सम्मिलित हैं। ये मानदंड वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन को बढ़ाते हुए आगामी जोखिमों को कम करते हैं।

मुद्रा प्रबंधन: भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह मुद्रा (नोट) जारी करता है, उनके संचलन पर नज़र रखता है, नकली मुद्रा का मुकाबला करता है, साथ ही मौद्रिक प्रणाली की अखंडता में योगदान देता है।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन: आर.बी.आई. विदेशी मुद्रा प्रबंधन के लिए दिशा–निर्देश बनाता और लागू करता है, जिससे बाहरी व्यापार और निवेश प्रवाह को सुगम बनाया जा सके। यह विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है और विदेशी मुद्रा लेन–देन की देख–रेख भी करता है।

नीति संचार और अनुसंधान: आर.बी.आई. जनता को वित्तीय संस्थानों और सरकार सहित विभिन्न हितधारकों को अपनी नीतियों, दिशा–निर्देशों और शोध निष्कर्षों के बारे में बताता है। यह पारदर्शिता प्रदान करता है और सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा देता है।

उपरोक्त सभी बिंदु वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, जिम्मेदार बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने और भारत में एक मजबूत वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा देने में आर.बी.आई. की व्यापक जिम्मेदारियों और कार्यों को दर्शाते हैं। आधिकारिक आर.बी.आई. वेबसाइट, आर.बी.आई. प्रकाशन, सरकारी रिपोर्ट और प्रतिष्ठित वित्तीय प्रकाशन जैसे प्रामाणिक स्रोत इन बयानों का समर्थन करने वाले और भी विस्तृत अंतर्दृष्टि और सबूत प्रदान कर सकते हैं।

विमुद्रीकरण में ग्रे मार्केट की भूमिका–

ग्रे मार्केट से अभिप्राय एक ऐसी अनौपचारिक व अनियमित बाजार को संदर्भित करना है जहां औपचारिक माध्यमों के बाहर वस्तुओं या सेवाओं का कारोबार होता है। भारत में विमुद्रीकरण के संदर्भ में, ग्रे मार्केट ने एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है,क्योंकि व्यक्तियों ने अपने अमान्य नोटों को बदलने या अवैध गतिविधियों में संलग्न होने के उद्देश्य से ही वैकल्पिक रास्तों का चयन किया। भारत के लिए वरदान या अभिशाप के रूप में इसकी भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए सूक्ष्म विश्लेषण:

कुछ व्यक्तियों के लिए वरदान

अमान्य मुद्रा का रूपांतरण: ग्रे मार्केट ने व्यक्तियों को अपने अमान्य मुद्रा नोटों को वैध नोटों में परिवर्तित करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण छूट पर या अवैध तरीकों से एक अवसर प्रदान किया।

धन का संरक्षण: कुछ लोगों ने विमुद्रीकरण अवधि के दौरान महत्त्वपूर्ण नुकसान को रोकने के लिए, अपने संचित धन और संपत्ति की रक्षा के लिए ग्रे मार्केट का उपयोग किया।

अर्थव्यवस्था और सरकार के लिए अभिशाप

ब्लैक मनी सर्कुलेशन: ग्रे मार्केट ने ब्लैक मनी के सर्कुलेशन को सुगम बनाया, क्योंकि लोग अवैध लेन–देन में लिप्त थे और जांच और करों से बचने का प्रयास करते थे।

औपचारिक अर्थव्यवस्था का कमजोर होना: ग्रे मार्केट के प्रसार ने लेन–देन को विनियमित चौनलों से दूर करके, कर राजस्व और आर्थिक विकास को प्रभावित करके औपचारिक अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया।

जाली मुद्रा: नकली मुद्रा के लिए ग्रे मार्केट एक प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है, जो मौद्रिक प्रणाली की अखंडता के लिए जोखिम पैदा करता है और नकली नोटों को खत्म करने के प्रयासों में बाधा डालता है।

सामाजिक और नैतिक चिंताएं

व्यापक सामाजिक आर्थिक विभाजन: ग्रे मार्केट गतिविधियों ने गैर–आनुपातिक रूप से अवैध चौनलों तक पहुंच वाले व्यक्तियों का पक्ष लिया, आय असमानता को बढ़ाया और समाज के हाशिए के वर्गों के बीच अन्याय की भावना पैदा की।

विश्वास की कमी: ग्रे मार्केट के प्रचलन ने औपचारिक वित्तीय प्रणाली और सरकारी पहलों व योजनाओं में जनता के भरोसे को खत्म कर दिया, जिससे एक पारदर्शी और जवाबदेह अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई।

यहां यह ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है कि विमुद्रीकरण के दौरान ग्रे मार्केट की भूमिका के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलू थे। जबकि इसने कुछ व्यक्तियों के लिए अस्थायी राहत प्रदान की तो वहीं दूसरी ओर इसका औपचारिक अर्थव्यवस्था, कर अनुपालन और सामाजिक आर्थिक समानता पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ा। वरदान या अभिशाप के रूप में इसके समग्र प्रभाव का आकलन करने के लिए विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और नैतिक आयामों पर इसके परिणामों के व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है।

विमुद्रीकरण: भारत के लिए वरदान या अभिशाप, व्यक्तिगत व विशेषज्ञों का मत

विमुद्रीकरण भारत के लिए एक वरदान या अभिशाप, यह निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञ राय, सर्वेक्षण और मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे प्रभावशाली उद्योगपतियों के व्यावसायिक

आंकड़ों के दृष्टिकोण सहित अन्य अनेक विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करना शामिल है। यहां महत्त्वपूर्ण है कि विमुद्रीकरण पर राय अलग–अलग हो सकती है।

मिश्रित विशेषज्ञ राय: विशेषज्ञों ने विमुद्रीकरण पर अलग–अलग विचार व्यक्त किए हैं। कुछ का मानना है कि इसके सकारात्मक प्रभाव थे जैसे कि काले धन पर अंकुश लगाना और डिजिटल लेन–देन को बढ़ावा देना, जबकि अन्य विशेषज्ञों द्वारा तर्क दिये गये कि लागत ने लाभ को कम कर दिया, अर्थव्यवस्था में व्यवधान और छोटे व्यवसायों और अनौपचारिक क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव का हवाला दिया; आदि–आदि।

विमुद्रीकरण के बाद किए गए कई सर्वेक्षणों ने कई तरह के दृ ष्टिकोण प्रस्तुत किए। जबकि कुछ सर्वेक्षणों ने नीति के लिए सार्वजनिक समर्थन का संकेत दिया, अन्य ने आर्थिक गतिविधि, रोजगार और उपभोक्ता भावना पर नकारात्मक प्रभाव को उजागर किया।

सफल व्यवसायिकों व विशेषज्ञों का दृष्टिकोण

मुकेश अंबानीरू रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने विमुद्रीकरण के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि इसका अर्थव्यवस्था के औपचारिककरण, पारदर्शिता और डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने नीति के दीर्घकालिक लाभों पर जोर दिया।

गौतम अदानी: अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने भी विमुद्रीकरण के लिए समर्थन व्यक्त किया, जिसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत के परिवर्तन को गति देने और भ्रष्टाचार को कम करने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला गया। अडानी ने कहा कि अल्पकालिक व्यवधानों की उम्मीद थी लेकिन दीर्घकालिक सकारात्मक परिणामों में वि वास था।

अरुण जेटली, भारत के पूर्व वित्त मंत्री: शैडो इकोनॉमी में काम करने वाला बहुत सारा पैसा अब बैंकिंग ढांचे का ही हिस्सा बन जाएगा। अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए बैंकों के पास बहुत अधिक पैसा होगा। निजी क्षेत्र का निवेश, जिसकी अब तक कमी थी, अब अर्थव्यवस्था में वापस आ जाएगा। एन.पी.ए. की समस्या से जूझ रहे बैंकों के पास कृषि, बुनियादी ढांचा क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, व्यापार और उद्योग के लिए उधार देने के लिए बहुत अधिक पैसा होगा।'

अरविंद विरमानी, सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार

श्काले धन को बाहर निकालने का यह एक उपयोगी तरीका है, यह देखते हुए कि नकदी का बड़ा प्रतिशत इन्हीं दो संप्रदायों में है। जिस तरह से इसे लागू किया गया वह आश्चर्य की बात नहीं है – इस तरह की कार्रवाइयां घोषित होने तक हमेशा गुप्त रहती हैं, ताकि अंदरूनी लोग बाहरी लोगों की कीमत पर जानकारी का लाभ न उठाएं।'

विभिन्न क्षेत्रों पर विविध प्रभाव

सकारात्मक पहलू: विमुद्रीकरण के समर्थकों का तर्क है कि इससे कर अनुपालन में वृद्धि हुई, भ्रष्टाचार में कमी आई और डिजिटल लेन–देन में वृद्धि हुई। उनका मानना है कि इसने अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप दिया, जिससे दीर्घकालिक लाभ हुआ।

नकारात्मक पहलू: आलोचक नकदी पर निर्भर क्षेत्रों में व्यवधान के कारण छोटे व्यवसायों, किसानों और दैनिक वेतन भोगियों पर प्रतिकूल प्रभाव की ओर इशारा करते हैं। उनका तर्क है कि लागत लाभ से अधिक है और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है।

यह विचार करना महत्त्वपूर्ण है कि विमुद्रीकरण पर राय समय के साथ विकसित हुई है और दीर्घकालिक प्रभाव पर बहस जारी है। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक टाइकून की व्यक्तिगत राय उनके स्वयं के विशिष्ट हितों और अनुभवों को दर्शा सकती है।

एक व्यापक समझ बनाने के लिए, जीडीपी विकास स्तर, रोजगार दर और वित्तीय समावेशन जैसे विभिन्न आर्थिक संकेतकों को जानने समझने के पश्चात् ही विशेषज्ञ विश्लेषणों, सर्वेक्षणों और डेटा की एक श्रृंखला की समीक्षा करने की सिफारिश की जाती है। यह दृष्टिकोण भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पर विमुद्रीकरण के समग्र प्रभाव के अधिक सूक्ष्म मूल्यांकन की अनुमति देता है।

भ्रान्तियां

समाज में अक्सर यह भी सुनने को मिल जाता है कि देश के विकास की गति धीमी हो गई है या यूं कहें ष्कई लोगों को डराया जा रहा है कि विकास धीमा हो रहा हैष् आमतौर पर ऐसी स्थिति को समाज में प्रसारित किया जा रहा है। जहॉं आर्थिक विकास में गिरावट या मंदी लोगों के बीच चिंता या चिंताजनक स्थिति देखने–सुनने को मिल रही है, उसका प्रभाव विभिन्न संदर्भो में लागू भी हो सकता है, जैसे राष्ट्रीय या वैश्विक अर्थव्यवस्था, एक विशिष्ट उद्योग या यहां तक कि एक कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन आदि।

जब विकास धीमा पड़ता है, तो यह अक्सर भविष्य के बारे में संदेह और अनिश्चितता को भी बढ़ावा देता है, जिसके चलते निवेशकों, व्यवसायों और आम जनता में चिंता और बेचौनी की स्थिति में भी वृद्धि होती है।

विकास में मंदी के कारण उत्पन्न भय और आशंका के कई परिणाम हो सकते हैं जैसे निवेशकों में नए निवेश करने के लिए सतर्कता, जिससे समग्र आर्थिक गतिविधियों में भी कमी आ सकती है। व्यवसाय की योजनाओं के विस्तारीकरण भर्ती या अनुसंधान और विकास में निवेश आदि में कटौती कर सकते हैं, जिससे संभावित नौकरी के नुकसान और नवाचार में कमी भी आ सकती है। उपभोक्ता भी अपने खर्च को लेकर अधिक सतर्क हो सकते हैं, जो आर्थिक विकास गति को और धीमा कर सकता है।

यह ध्यान रखने वाला तथ्य यह है कि समय के साथ आर्थिक विकास में स्वाभाविक रूप से उतार–चढ़ाव तो अवश्य होता है, क्योंकि मंदी या संकुचन की अवधि और अवस्था में आर्थिक चक्र प्रक्रिया एक सामान्य हिस्सा है। हालाँकि, यदि मंदी गंभीर अवस्था को प्राप्त हो या लंबी अवधि से चल रही है, तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

नीति निर्माता और अर्थशास्त्री आर्थिक संकेतो की बारीकी से निगरानी करते हुए विकास में मंदी के प्रभाव को कम करने के उपायों को लागू करते हैं। इन उपायों में सरकारी व्यय या कर कटौती जैसी राजकोषीय नीतियां, ब्याज दर समायोजन जैसी मौद्रिक नीतियां या दीर्घकालिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अनेक संरचनात्मक सुधार शामिल हो सकते हैं।

कुल मिलाकर, एक धीमी विकास दर वास्तव में चिंताओं और अनिश्चितता पैदा कर सकती है, लेकिन यह नीति–निर्माताओं, व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और टिकाऊ और लचीला आर्थिक विकास की दिशा में काम करने का अवसर भी है।

आर.बी.आई. भारत का केंद्रीय बैंक है और मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने, वित्तीय प्रणाली को विनियमित करने और टिकाऊ आर्थिक विकास का समर्थन करने वाली नीतियों को तैयार करने में

महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्थिक मंदी के समय में आर.बी.आई. अक्सर स्थिति का आकलन करने और प्रभाव को कम करने और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त नीतियों को लागू करने के लिए उपायों को अपनाकर योजना लागू करता है। विश्लेषण के आधार पर, आर.बी.आई. मंदी को दूर करने के लिए उपयुक्त मौद्रिक नीतियों को तैयार और क्रियान्वयन कर सकता है। इन नीतियों में उधार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दरों में समायोजन, तरलता प्रबंधन के उपाय या नियामक परिवर्तन शामिल हो सकते हैं। आरबीआई विकास का समर्थन करने वाली राजकोषीय नीतियों को लागू करने के लिए सरकार के साथ समन्वय में भी काम कर सकता है, जैसे लक्षित खर्च, कर सुधार या विशिष्ट क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन।

यहां पर यह ध्यान रखना अति महत्त्वपूर्ण है कि मंदी से निपटने के लिए सरकार, नियामक निकायों, वित्तीय संस्थानों और व्यवसायों सहित कई हितधारकों को शामिल करते हुए एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता होती है। आर.बी.आई. का विश्लेषण और उसके बाद की नीतिगत कार्यवाही आर्थिक चुनौतियों के माध्यम से संचालित करना सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक रणनीति का महत्त्वपूर्ण एवं अनिवार्य हिस्सा हैं।

नोटबंदी: सर्वेक्षण आधारित प्रभाव

यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि सर्वेक्षण के परिणाम कार्यप्रणाली, नमूना आकार और सर्वेक्षण के समय के आधार पर भिन्न–भिन्न हो सकते हैं। विमुद्रीकरण के बाद किए गए कई सर्वेक्षणों के आधार पर अलग–अलग क्षेत्रों में परिणामस्वरूप कुछ प्रमुख प्रभावित स्थिति देखने–सुनने को मिली,जो प्रतिक्रिया उजागर हुई, जो यहां इस शोध–पत्र में वर्णित हैंरू

मिश्रित जनमत

कुछ सर्वेक्षणों ने संकेत दिया कि आबादी के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से ने विमुद्रीकरण का समर्थन किया, यह विश्वास करते हुए कि इससे काले धन, भ्रष्टाचार और जालसाजी पर अवश्य अंकुश लगेगा। वहीं दूसरी ओर अन्य सर्वेक्षणों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आबादी के एक बड़े वर्ग ने विमुद्रीकरण को महत्त्वपूर्ण असुविधा और आर्थिक व्यवधान के रूप में देखा।

आर्थिक प्रभाव

सर्वेक्षणों ने बताया कि विमुद्रीकरण का आर्थिक विकास, रोजगार और अनौपचारिक क्षेत्र पर अल्पकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हालाँकि, दीर्घकालिक प्रभाव पर अलग–अलग राय रही, कुछ सर्वेक्षणों में संभावित सकारात्मक परिणामों का सुझाव दिया गया था जैसे कर अनुपालन में वृद्धि और डिजिटल भुगतान की ओर एक जबरदस्त तरीके से धक्का दिया।

क्षेत्र–विशिष्ट प्रभाव

सर्वेक्षणों ने संकेत दिया कि कृषि, छोटे व्यवसायों और अनौपचारिक क्षेत्रों जैसे नकद लेन–देन पर भारी निर्भर क्षेत्रों ने विमुद्रीकरण की प्रारंभिक अवधि के दौरान महत्त्वपूर्ण व्यवधानों का अनुभव किया। रियल एस्टेट और सोना जैसे क्षेत्रों पर प्रभाव भी अलग–अलग था, कुछ सर्वेक्षणों ने लेन–देन में मंदी का सुझाव दिया जबकि अन्य ने अधिक पारदर्शिता की ओर बदलाव का संकेत दिया।

वित्तीय समावेशन और डिजिटल लेन–देन में प्रभाव

कुछ सर्वेक्षणों ने विमुद्रीकरण के बाद डिजिटल भुगतान विधियों, मोबाइल वॉलेट और ऑनलाइन लेन–देन को अपनाने में वृद्धि की सूचना दी। हालाँकि, डिजिटल डिवाइस के बारे में कुछ लोगों द्वारा चिंताएँ व प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त की गईं, क्योंकि सम्पूर्ण आबादी के कुछ विशेष व वरिष्ठ नागरिकों एवं विशेष वर्ग में तकनीकी ज्ञान का अभाव के चलते , विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों तक पहुँचने और उपयोग करने में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा; जैसे दृ

अल्पकालिक प्रभाव

2016 में विमुद्रीकरण ने आर्थिक गतिविधियों में एक अस्थायी व्यवधान पैदा किया, विशेष रूप से कृषि, खुदरा और अनौपचारिक व्यवसायों जैसे नकदी पर निर्भर क्षेत्रों में नीति के क्रियान्वयन के तत्काल बाद ही उच्च मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों को वापस लेने से खपत, उत्पादन और रोजगार प्रभावित हुआ।

दीर्घकालिक प्रभाव

भारत के आर्थिक विकास पर विमुद्रीकरण का दीर्घकालिक प्रभाव बहस और विश्लेषण का विषय है। यह विचार करना आवश्यक है कि विभिन्न कारक आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं, और विमुद्रीकरण कई में से एक है। समर्थकों का तर्क है कि विमुद्रीकरण के सकारात्मक परिणाम थे जैसे कर अनुपालन में वृद्धि, अर्थव्यवस्था का औपचारिककरण वास्तव में मशीनी तकनीक आधारित लेन–देन की ओर एक अप्रत्याशित धक्का देने के जैसा है,, जो भविष्य में निरंतर आर्थिक विकास में योगदान कर सकता है। आलोचकों का कहना है कि अल्पकालिक व्यवधान और नकदी लेन–देन पर अत्यधिक निर्भर क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव से आर्थिक विकास में बाधा आ सकती है। उनका तर्क है कि विमुद्रीकरण के लाभों ने लागतों को पूरी तरह से अव्यवस्थित नहीं किया होगा। भारत के आर्थिक विकास पर विमुद्रीकरण के प्रभाव के बारे में अधिक सटीक और ताजा व वर्तमान आकंड़ों पर आधारित जानकारी प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठित अनुसंधानिक संस्थानों, वित्तीय संगठनों या सरकारी स्रोतों द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों और विश्लेषणों के संदर्भों का व्यापक अध्ययन किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

साधारण जन–समुदाय की प्रतिक्रिया

भारत में 2016 में लागू किए गए विमुद्रीकरण ने स्थानीय आबादी के बीच कई प्रकार की राय और भावनाओं को उजागर किया। महत्त्वपूर्ण यह है कि विमुद्रीकरण पर सार्वजनिक दृष्टिकोण व व्यक्तिगत अनुभवों में अन्तर परिस्थितियों के आधार पर भिन्न–भिन्न हो सकते हैं। यहाँ स्थानीय आबादी के विभिन्न वर्गों द्वारा व्यक्त किए गए सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोणों का एक सामान्य अवलोकन प्रस्तुत लेख में दर्शाया गया है

सकारात्मक दृष्टिकोण

भ्रष्टाचार से उत्पन्न धन पर अंकुश: कुछ लोगों ने विमुद्रीकरण का समर्थन किया, यह विश्वास करते हुए कि यह नियम काले धन, भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों से प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में सहायक सिद्ध होगा।

तकनीकी परिवर्तन: कई लोगों ने नोटबंदी को डिजिटल लेन–देन को अपनाने और अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने के एक उत्प्रेरक के रूप में देखा। उन्होंने इसे नकदी पर निर्भरता कम करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक अच्छे कदम के रूप में देखा।

नकारात्मक दृष्टिकोण

असुविधा और व्यवधान: उच्च मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों को अचानक वापस लेने के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने असुविधा का अनुभव किया। इसने आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं तक पहुँचने सहित उनके दैनिक जीवन को प्रभावित किया।

वित्तीय प्रभाव: कृषि, छोटे व्यवसायों और अनौपचारिक क्षेत्र जैसे नकदी पर बहुत अधिक निर्भर क्षेत्रों में व्यक्तियों ने अक्सर अपनी आजीविका और रोजगार के अवसरों पर अल्पकालिक नकारात्मक प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की।

विमुद्रीकरण के अन्य विविध अनुभव

शहरी बनाम ग्रामीण विभाजन: विमुद्रीकरण पर दृष्टिकोण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच बिल्कुल अलग था। जबकि कुछ शहरी निवासियों ने डिजिटल लेनदेन को अनुकूलित करने के लिए इसे अपेक्षाकृत प्रबंधनीय पाया, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग बुनियादी ढांचे और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक सीमित पहुंच के चलते कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

सामाजिक आर्थिक प्रभाव: विमुद्रीकरण का प्रभाव विभिन्न आय समूहों में अलग–अलग था। निम्न–आय पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को अक्सर अधिक महत्वपूर्ण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जबकि बेहतर वित्तीय संसाधनों वाले लोग परिवर्तनों को नेविगेट करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित थे।
यहां यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि ये विविध दृष्टिकोण केवल सामान्य अवलोकन हैं और पूरी आबादी की राय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। विमुद्रीकरण पर स्थानीय लोगों के विचारों की व्यापक जानकारी व समझ हासिल करने के लिए, उस अवधि के दौरान जन भावनाओं में उत्पन्न विचारों लिए विशेष रूप से किए गए सर्वेक्षणों, साक्षात्कारों या अध्ययनों का संदर्भ लेने की सलाह दी जाती है।

विमुद्रीकरण: वैश्विक परिप्रेक्ष्य

- **एशिया:** भारत और म्यांमार जैसे एशियाई देशों ने महत्त्वपूर्ण विमुद्रीकरण अभियानों का अनुभव किया है। इन पहलों का उद्देश्य भ्रष्टाचार, जालसाजी और अवैध वित्तीय प्रवाह से निपटना है। हालांकि, उनके प्रभाव अलग–अलग हैं, मिश्रित परिणामों के साथ अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के मामले में।

- **भारत:** 2016 में भारत का विमुद्रीकरण अभियान एक महत्त्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में कार्य करता है। सांख्यिकीय आंकड़ों से पता चलता है कि भारत सरकार ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को अमान्य कर दिया, जो देश की मुद्रा का लगभग 86ः हिस्सा था। इस कदम का उद्देश्य भ्रष्टाचार, जालसाजी और काले धन के संचलन पर अंकुश लगाना था। कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में अल्पकालिक रुकावटें आईं, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में गिरावट और खपत में कमी आई। हालांकि, इस अवधि के दौरान डिजिटल भुगतान लेन–देन में काफी वृद्धि देखी गई, जो कैशलेस लेन–देन की ओर एक बदलाव को दर्शाता है।

- **अफ्रीका:** जिम्बाब्वे और नाइजीरिया सहित कई अफ्रीकी देशों ने अत्यधिक मुद्रास्फीति को संबोधित करने, अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने और अवैध वित्तीय गतिविधियों से निपटने के लिए विमुद्रीकरण उपायों को लागू किया है। आर्थिक स्थिरता और वित्तीय समावेशन प्राप्त करने में सफलता की अलग–अलग डिग्री के साथ परिणाम विविध रहे हैं।

- **लैटिन अमेरिका:** वेनेजुएला जैसे देशों ने अत्यधिक मुद्रास्फीति को दूर करने और अपनी वित्तीय प्रणालियों में विश्वास बहाल करने के लिए विमुद्रीकरण का उपयोग किया है। हालाँकि, आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने और मुद्रास्फीति को कम करने में इन उपायों की प्रभावशीलता सीमित रही है।

तालिका 1

राष्ट्र का नाम	विमुद्रीकरण नीति लागू वर्ष
इंडोनेशिया	1965
उरुग्वे	1974
घाना	1982
नाईजीरिया	1984
म्यांमार	1987
सोवियत संघ	1990
यूरोपीय संघ	2002
भारत	2016, 2023
वेनेजुएला	2016.17
ज़िम्बाब्वे	2019

वैश्विक विमुद्रीकरण उपायों को विविध प्रेरणाओं और अलग–अलग परिणामों के साथ लागू किया गया है। जबकि विमुद्रीकरण से अल्पकालिक व्यवधान और चुनौतियाँ हो सकती हैं, यह डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन के अवसर भी प्रस्तुत करता है। दुनिया भर में विमुद्रीकरण के प्रयासों से सीखे गए क्षेत्रीय दृष्टिकोण और सबक को समझना भविष्य में अधिक प्रभावी नीतियों और रणनीतियों के विकास में योगदान कर सकता है।

विमुद्रीकरण भारत के लिए वरदान या अभिशाप

इस बारे में शब्दों में कहना ,एक जटिल अभिव्यक्ति होगी, क्योंकि अलग–अलग व्यक्तियों द्वारा इस विषय पर राय भी भिन्न–भिन्न रहती है। समग्र प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न कारकों और दृष्टिकोणों पर विचार करते हुए कुछ महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर सारांश के साथ निष्कर्ष कुछ इस प्रकार है रू

विमुद्रीकरण के संभावित वरदान

- **काले धन पर अंकुश लगाना:** विमुद्रीकरण का उद्देश्य उच्च मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों को अमान्य करके; काले धन, भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों से निपटना है।

- **डिजिटल परिवर्तन:** नीति का उद्देश्य डिजिटल लेन–देन को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाना और नकदी पर निर्भरता को कम करना है, जिससे संभावित रूप से पारदर्शिता और कर अनुपालन में वृद्धि होगी।

- **दीर्घकालिक लाभ:** समर्थकों का तर्क है कि अधिक पारदर्शी और जवाबदेह वित्तीय प्रणाली के संदर्भ में दीर्घकालिक लाभ के लिए ये अल्पकालिक व्यवधान अत्यंत आवश्यक थे।

विमुद्रीकरण के संभावित अभिशाप

- **आर्थिक व्यवधान:** उच्च मूल्य की मुद्रा की अचानक वापसी से अल्पकालिक व्यवधान उत्पन्न हुए, विशेष रूप से नकद लेन–देन पर निर्भर क्षेत्रों को प्रभावित किया। छोटे व्यवसायों, कृषि और अनौपचारिक क्षेत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
- **जनता को असुविधा:** विमुद्रीकरण के तत्काल प्रभाव से जनता को असुविधा हुई, जिसमें नकदी तक पहुँचने, आवश्यक सामान खरीदने और दैनिक लेनदेन करने में कठिनाइयाँ शामिल थीं।

- **असमान प्रभाव:** नीति का प्रभाव समान रूप से वितरित नहीं किया गया था, समाज के सीमांत वर्गों के साथ, विशेष रूप से बैंकिंग सुविधाओं तक सीमित पहुंच वाले लोग, असमान रूप से प्रभावित हो रहे थे।

उपरोक्त वर्णित सभी परिणामों और विविध मतों को देखते हुए, यह निष्कर्ष निकालना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है कि नोटबंदी भारत के लिए वरदान या अभिशाप रही। विभिन्न हितधारकों ने अपनी परिस्थितियों के आधार पर अलग–अलग परिणामों का अनुभव किया ,इसके अलावा, विमुद्रीकरण के दीर्घकालिक प्रभाव अभी भी सामने आ रहे हैं, जिससे इसके समग्र प्रभाव का सटीक आकलन करना कठिन है।

अतः एक व्यापक निष्कर्ष निकालने के लिए, आर्थिक संकेतकों, क्षेत्र–विशिष्ट विश्लेषणों, जन–भावना और विशेषज्ञों की राय सहित कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचार करना उतना ही आवश्यक है जितना कि विमुद्रीकरण के दीर्घकालिक प्रभावों पर चल रहे मूल्यांकन और अध्ययन भारत की अर्थव्यवस्था और समाज के लिए इसके समग्र प्रभाव में और विशेषकर अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। उपरोक्त वर्णित सभी जानकारी मेरी अपनी व्यक्तिगत चेतना और अनुभव के आधार पर वैचारिक रूपों को शब्दों में पिरोने का प्रयास किया गया है।

सन्दर्भ सूची

1. Note-Bandi (DemonetizationAnd India's Elusive Chase for Black Money] R- ramakumar ,2018)
2. Dijitala IndiyaAura Bharat]Ananya Prakasana] Viraga Gupta &2017
3. नोटबन्दी– एक महायज्ञ; 2017, राजीव पराशर।
4. शिक्षा का व्यापार इमोशनल अत्याचार – पेज 50, तेजपाल शर्मा,2018
5. समय का सच – आर. के.सिन्हा, 2020
6. वैश्विक युग का भारत: आर्थिक सुधार और समावेशी विकास, डॉ वन्दना डांगी,
7. Trends in Hindi Linguistics & Ghanshyam Sharma]Rajesh Bhatt] 2018
8. Naukari Nahin] Business Idea Dhoondho] N-Raghuraman] 2020
9. Aahwaan & page 118]Pt- Bheemnarayan Pateriya] 2021